| | |
|---|---|
| 3. Container Corpn. of India | 14.12 |
| 4. Steel Authority of India Ltd. | 13.37 |
| GRAND TOTAL | 168.62 |

**Withdrawal of Law/Constitutional provision extended to Jammu & Kashmir**

1871. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposal was received from the State Government, during the period 1975 to 1986 and 1987 to 1989 regarding withdrawal of any law or constitutional provision extended to Jammu & Kashmir during the period prior to 1975; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The Government of. Jammu & Kashmir has stated that the State Government did not propose withdrawal of any law or Constitutional provision extended to the State during the period prior to 1975.

**मध्य प्रदेश में शहरी विकास संबंधी "मेगनेट टाउन" योजना**

1872. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों को "मेगनेट टाउन"के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव हैं;

(ख) शहरों के ऐसे विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजना का शहर-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किन-किन शहरों को शामिल किया गया हैं;और

(घ) चालू वर्ष में इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शहर-वार कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के शहरी विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन)**: (क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर सिटी को सम सुविधा सम्पन्न कस्बे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव हैं।

(ख) ग्वालियर के लिये विकास कोष स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने मार्च 1992 में 1 करोड़ रू. दिये थे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी मई 1992 में 1 करोड़ रू. दिये थे।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव में कोई अन्य सिटी/कस्बा शामिल नहीं हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने ग्वालियर विकास कोष के लिये चालू वित्त वर्ष हेतु 2 करोड़ रू. का प्रावधान किया हैं।

**Privatisation of CSD**

1873. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the steps proposed to privatise the commercial operations of Canteen Stores Department;

(b) whether more transparency has been introduced in the functioning of Canteen Stores Department in 1994-95; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) There is no proposal to privatise the operations of the Canteen Stores Department (CSD).

The functioning of the CSD is periodically reviewed at different levels so as to ensure greater efficiency and transparency.